

(b) The cost of education including fees, books and uniforms will be borne by the Centre in respect of centrally administered and aided schools and the States in respect of schools controlled by them

(c) Two members of each family of a jawan killed in action may be appointed without registration at the Employment Exchange to Class III/IV post in Central Government posts filled by direct recruitment.

(d) In Public Sector Enterprises reservation of 17½% of posts in Class III and 27½% in Class IV have been made for ex-servicemen and dependents of service personnel killed in action

2 Pay and allowances for December 1971 and January 1972 have been disbursed in full in almost all cases. Family Pension/Dependent Pension has already been authorised in a very large number of cases. In cases in which claims for Family Pension/Dependent Pension are still being processed, Pending Enquiry Awards have been sanctioned.]

अधिकृत काश्मीर में सैनिक प्रशिक्षण के लिए लोगो की भर्ती

***195 श्री डी० के० पटेल
श्री वी० के० सखलेचा :
श्री बाबु भाई एम० चिनाई**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्टूबर, 1972 के डेली टेलीग्राफ लंदन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को स्वयं सेवकों के रूप में भर्ती किया जा रहा है और उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†[ENROLMENT OF PERSONS FOR MILITARY TRAINING IN OCCUPIED KASHMIR

***195. SHRI D K PATEL
SHRI V K SAKHALECHA
SHRI BABUBHAI M CHINAI.**

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state

(a) whether Govt.'s attention has been invited to a news item published in the Daily Telegraph, London dated the 24th April, 1972 to the effect that persons between 18 and 40 years of age in the Pak-occupied territory of Kashmir are being enrolled as volunteers and military training is being imparted to them, and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard ?]

**रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क)
जी हा, श्रीमन् ।**

(ख) हमारे रक्षा उपायो का पुनरीक्षण करते समय पाकिस्तान में इस प्रकार की हुई सभी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है ।

†[THE MINISTER OF DEFENCE
(SHRI JAGJIVAN RAM) (a) Yes, Sir

(b) All such developments in Pakistan are taken into consideration in reviewing our defence measures.]

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों की खरीद

***196 श्रीमति लक्ष्मी कुमारी चूडावत :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम प्रति माह प्रॉवेट कम्पनियों के करोड़ों रुपये के शेयर खरीदता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन निजी कम्पनियों में भी ज्यादातर शेयर पचहत्तर मोनोपोली घरानों की कम्पनियों के ही खरीदे जाते हैं,

†[] English translation.

(ग) यदि हां तो क्या सरकार निगम को यह आदेश देगी कि वह मोनोपोली घरानों की कम्पनियों के शेयर खरीदना बन्द कर दे; और

(घ) क्या इस प्रकार के निवेश की बजाय छोटे तथा मध्यम वर्गीय आवास योजनाओं में धन लगाना ज्यादा हितकर नहीं होगा ?

†[PURCHASE OF SHARES BY L.I.C.]

*196. SHRIMATI LAXMI KUMARI CHUNDAWAT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation purchases shares of private companies worth crores of rupees every month;

(b) whether it is also a fact that out of the shares of these private companies majority of the shares are purchased from those companies which belong to the seventy-five monopoly houses;

(c) if so, whether Government would direct the corporation to stop purchasing the shares of the companies owned by monopoly houses; and

(d) whether the diversion of such investments to small and medium housing schemes would not be more viable ?]

वित्त मंत्री (श्री य० ब० चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों में कम्पनियों के, (जिनमें एकाधिकार समूहों की कम्पनियां भी शामिल हैं) शेयरों में नीचे दिये अनुसार निवेश किये हैं।

लाख रुपयों में

वर्ष	निवेश की गई कुल रकम	एकाधिकार समूहों की कम्पनियों में निवेश की गई रकम
1967-68	312.58	153.11
1968-69	350.28	187.33
1969-70	305.37	220.68
1970-71	117.12	38.29
1971-72	240.99	102.67

(ग) और (घ) पूंजी की सुरक्षा के साथ साथ अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिये जीवन बीमा निगम के पास बहुमुखी निवेश के आयोजन रहते हैं। शेयरों को बाजार से खरीदने में कोई सहायता का रूप नहीं बनता और इस बारे में विचारणीय बात केवल सुरक्षा का स्वरूप एवं लाभ ही है। सरकार द्वारा स्वीकृत नयी परियोजनाओं को दिये गये सीधे अंशदान कुल सहायता के भाग होते हैं और उससे वित्तीय संस्थाएं सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की नीतियों पर प्रभाव डालने में समर्थ होती हैं। जीवन बीमा निगम के निवेश आयोजनों में आवास निर्माण को पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसलिए जीवन बीमा निगम को, एकाधिकार समूहों की कम्पनियों के शेयरों की खरीद रोकने के आदेश देने का प्रस्ताव नहीं है।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.]

STATEMENT

(a) and (b) The LIC's investments in shares of companies (including those belonging to monopoly groups) during the last five years are given below :—

(In lakhs of rupees)

Year	Total amount invested	Amount invested in companies belonging to Monopoly Groups
1967-68	312.58	1'3.11
1968-69	300.28	187.33
1969-70	305.37	220.68
1970-71	117.12	38.29
1972-72	240.99	102.67

(c) and (d) The LIC maintains a well diversified investment portfolio to earn the maximum yield consistent with the safety of capital. Market purchases of shares do not constitute assistance and the only relevant consideration is the nature of security and yield. Direct subscriptions form part of the total assistance given to new projects approved by Government and enable the financial institutions to influence the policies of the assisted concerns. Housing already occupies an important position in the investment portfolio of the LIC. It is, therefore, not proposed to direct the LIC to stop purchasing shares of companies belonging to the Monopoly Groups.]

रक्षा संबंधी सामग्री का उत्पादन तथा उसकी सप्लाई करने वाली फर्में

*197. श्री सूरज प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रक्षा संबंधी सामग्री का उत्पादन तथा उसकी सप्लाई करने के लिये कितनी फर्मों को टेंडर दिये गये और किन-किन फर्मों ने अभी तक न तो सामान सप्लाई किया है और न ही उस राशि को लौटाया है जो उन्हें अग्रिम के रूप में दी गई थी; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†[NUMBER OF FIRMS FOR PRODUCTION AND SUPPLY FOR DEFENCE PURPOSES

*197. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of firms which were given tenders for the production and supply of goods for defence purposes during the last two years and the names of the firms which have neither supplied the goods nor returned the advances given to them so far; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?]

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रक्षा सेवाओं के लिए बहुत मामलों में वस्तुएं, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रक्षा सेवा मुख्यालयों, स्टोर डिपुओं, आर्डनेंस कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योग संस्थानों द्वारा सीधे उपलब्ध की जाती है। शेष वस्तुएं डी जी एस एण्ड डी द्वारा अथवा रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध की जाती हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे ऐसी मदें हैं जिनका निर्माण व्यवस्थित रूप से हो रहा है अथवा क्या उन्हें देश में पहली बार निर्मित किया जा रहा है। डी जी एम एण्ड डी, तीनों सेवा मुख्यालयों, आर्डनेंस कारखानों, स्टोर डिपुओं तथा देश भर में फैली रक्षा संस्थानों से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में समय लगेगा। इसलिए निम्न-लिखित उत्तर, रक्षा पूर्ति विभाग द्वारा आर्डर दी गई मदों की स्थिति तक ही सीमित है।

2. जिन फर्मों को टेंडर जारी किये गए हैं उनकी सख्या काफी बड़ी है और सम्भवतः माननीय सदस्य का यह आशय नहीं है कि उन फर्मों की सख्या बताई जाए जिन्हें टेंडर दिये गये

†[] English translation.